



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 307]

नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 3, 2014/कार्तिक 12, 1936

No. 307]

NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 3, 2014/KARTIKA 12, 1936

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुम्बई, 27 अक्टूबर, 2014

सं. टीएमपी/62/2009-पीपीटी.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48, 49 और 50 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्वारा संलग्न आदेशानुसार, पारादीप पत्तन न्यास के मौजूदा दरमानों की वैधता को विस्तारित करता है।

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

मामला सं. टीएमपी/62/2009-पीपीटी

कोरम:

- (i) श्री टी.एस. बालासुब्रह्मण्यन, सदस्य (वित्त)
- (ii) श्री चन्द्र भान सिंह, सदस्य (अर्थशास्त्र)

आदेश

(सितम्बर 2014 के 30वें दिन पारित)

यह आदेश पारादीप पत्तन न्यास (पीपीटी) के मौजूदा दरमानों की वैधता को विस्तारित करने से संबंधित है।

2. पीपीटी का मौजूदा दरमान इस प्राधिकरण द्वारा आदेश सं. टीएमपी/62/2009-पीपीटी दिनांक 25 मार्च, 2011 द्वारा पिछली बार अनुमोदित किया गया था जिसे 23 मई, 2011 को भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया था। इस आदेश ने दरमान की वैधता 31 मार्च, 2013 तक निर्धारित की थी। इस प्राधिकरण ने पीपीटी के दरमान की वैधता को कई बार विस्तारित किया था; आखिरी बार आदेश दिनांक 4 जुलाई, 2014 द्वारा 30 सितम्बर, 2014 तक विस्तारित किया जा रहा है।

3. पीपीटी ने मौजूदा दरमान के संशोधन के लिए अपना प्रस्ताव 27 अगस्त, 2012 को दाखिल किया था जिसे प्रशुल्क मामला के रूप में पंजीकृत किया गया था और विचार-विमर्श किया गया था। इस प्रस्ताव की आंतरिक तौर पर संवीक्षा की गई है और इस मामले में संयुक्त सुनवाई 25 फरवरी, 2013 को आयोजित की गई थी।

4.1. जब यह मामला इस प्राधिकरण के अंतिम विचार के लिए तैयार किया जा रहा था, पीपीटी ने अपने पत्र दिनांक 30 अक्टूबर 2013 द्वारा, निवेदन किया था कि चूंकि वित्तीय वर्ष 2012-13 पहले ही समाप्त हो चुका था और वर्ष 2012-13 के लिए वास्तविक आंकड़े उपलब्ध हैं जिनपर विचार करना होगा क्योंकि प्रहस्तित किए जाने के लिए अनुमानित कार्गो मिश्रण में बदलाव हुआ है और तेल कार्गो में काफी वृद्धि हुई है। इसके अलावा, 12 अक्टूबर, 2013 को भयानक चक्रवात की वजह से, पत्तन को उसकी सम्पत्तियों का नुकसान हुआ है जोकि लगभग 82.71 करोड़ अनुमानित किया गया है। पीपीटी ने कहा है कि यदि हुए नुकसानों की भरपाई के लिए अनुदान हेतु भारत सरकार से इसके अनुरोध पर विचार नहीं किया जाता है तो पीपीटी को अपने आंतरिक संसाधनों से भरपाई लागत को पूरा करना होगा जिससे आंतरिक संसाधन प्रभावित होंगे।

4.2. उपर्युक्त स्थिति के मद्देनजर, पीपीटी ने अपने दरमान के सामान्य संशोधन के लिए संशोधित प्रस्ताव दाखिल करने के लिए तीन महीने के समय की मांग की थी। पीपीटी द्वारा उल्लिखित कारणों से, पत्तन को उसका संशोधित प्रस्ताव दाखिल करने के लिए 31 जनवरी, 2014 तक का समय दिया गया था। चूंकि प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ था, इसलिए पीपीटी को हमारे पत्र दिनांक 17 फरवरी, 2014 द्वारा उसका संशोधित प्रस्ताव दाखिल करने के लिए अनुस्मरण करवाया गया था। पीपीटी ने अपने पत्र दिनांक 28 फरवरी, 2014 द्वारा बताया था कि वह अपना प्रस्ताव सरकार द्वारा अंतिम रूप दिए जाने वाले संभावित नए दिशानिर्देशों के अनुसार अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा। 2005 के लागू प्रशुल्क दिशानिर्देशों के अधीन अपना प्रस्ताव दाखिल करने के लिए पीपीटी को सलाह देते हुए इस संबंध में पीपीटी को एक पत्र 1 मई, 2014 जारी किया गया था। 30 सितम्बर, 2014 तक मौजूदा दरमान की वैधता को विस्तारित किए जाने के समय, पीपीटी को 2005 के लागू प्रशुल्क दिशानिर्देशों के अधीन अपना संशोधित प्रस्ताव 31 अगस्त, 2014 तक दाखिल करने की सलाह भी दी गई थी। पीपीटी से संशोधित प्रस्ताव की अभी भी प्रतीक्षा है। अतः, पीपीटी को सलाह दी जाती है कि अपना संशोधित प्रस्ताव तत्काल दाखिल करें।

5. इसी बीच, मौजूदा दरमान की विस्तारित वैधता 30 सितम्बर, 2014 को समाप्त हो गई थी। यह स्वीकार करते हुए कि पीपीटी को अपना संशोधित प्रस्ताव अभी दाखिल करना है और पीपीटी द्वारा दाखिल (किए जाने वाले) संशोधित प्रस्ताव की प्राप्ति के बाद अंतिम विचार के लिए मामला तैयार करने में समय लगेगा, यह प्राधिकरण पीपीटी के मौजूदा दरमान की वैधता को 31 दिसम्बर, 2014 तक अथवा संशोधित दरमान के कार्यान्वयन की प्रभावी तारीख तक, जो भी पहले हो, विस्तारित करता है।

6. यदि स्वीकार्य लागत और अनुमत प्रतिलाभ से अधिक कोई अतिरिक्त अधिशेष 1 अप्रैल, 2013 के बाद प्रोद्भूत होता है तो इसके कार्यानिष्पादन की समीक्षा के दौरान, ऐसा अतिरिक्त अधिशेष अगले चक्र के लिए निर्धारित किए जाने वाले प्रशुल्क में पूर्णतः समायोजित किया जाएगा।

टी. एस. बालासुब्रह्मण्यन, सदस्य (वित्त)

[विज्ञापन-III/4/असा./143/2014]

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

NOTIFICATION

Mumbai, the 27th October, 2014

No. TAMP/62/2009-PPT.—In exercise of the powers conferred under Sections 48, 49 and 50 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby extends the validity of the existing Scale of Rates of the Paradip Port Trust as in the Order appended hereto.

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

Case No. TAMP/62/2009-PPT

QUORUM

- (i) Shri T.S. Balasubramanian, Member (Finance)
- (ii) Shri Chandra Bhan Singh, Member (Economic)

ORDER

(Passed on this 30th day of September, 2014)

This Order relates to the extension of the validity of the existing Scale of Rates of the Paradip Port Trust (PPT).

2. The existing Scale of Rates (SOR) of the PPT was last approved by this Authority vide Order No. TAMP/62/2009-PPT dated 25 March, 2011 which was notified in the Gazette of India on 23 May, 2011. The Order prescribed the validity of the SOR till 31 March, 2013. This Authority has extended the validity of SOR of PPT on couple of occasions; the last extension being till 30 September, 2014 vide its Order dated 4 July, 2014.

3. The PPT has filed its proposal for revision of the existing SOR on 27 August, 2012 which was registered as tariff case and taken on consultation. The proposal has been internally scrutinized and joint hearing in this case was held on 25 February, 2013.

4.1. When the case was being firmed up for final consideration of this Authority, the PPT, vide its communication dated 30 October, 2013, submitted that as the financial year 2012-13 was already over and the actual figures for the year 2012-13 are available which may have to be considered since the cargo mix estimated to be handled has undergone a change and the oil cargo has increased substantially. Moreover, due to severe cyclone on 12 October, 2013, port has suffered damages to its properties which is estimated to be around ₹82.71 crores. The PPT has stated that if its request to Government of India for a grant to restore the damages caused is not considered, the PPT will have to meet the restoration cost from its internal resources which will affect its internal resources.

4.2. In view of the above position, the PPT had sought three months' time to submit a revised proposal for general revision of its SOR. For the reasons stated by PPT, the port was allowed time till 31 January, 2014 to file its revised proposal. Since the proposal was not received, the PPT was reminded to file its revised proposal vide our letter dated 17 February, 2014. The PPT vide its letter dated 28 February, 2014 has stated that it will submit its proposal as per new guidelines likely to be finalised by the Government. A letter to PPT in this regard advising PPT to file its proposal

under the applicable tariff guidelines of 2005 was issued on 1 May, 2014. While extending the validity of the existing SOR till 30 September, 2014, the PPT was also advised to file its revised proposal by 31 August, 2014 under the applicable tariff guidelines of 2005. The revised proposal from PPT is still awaited. The PPT, therefore, is advised to file its revised proposal immediately.

5. In the meantime, the extended validity of the existing SOR expired on 30 September, 2014. Recognizing that the PPT is yet to file its revised proposal and it will take time for the case to mature for final consideration after receipt of the revised proposal (to be) filed by the PPT, this Authority extends the validity of the existing SOR of the PPT from the date of its expiry till 31 December, 2014 or till the effective date of implementation of the revised Scale of Rates, whichever is earlier.

6. If any additional surplus over and above the admissible cost and permissible return accrues to the PPT post 1 April, 2013, during the review of its performance, such additional surplus will be fully adjusted in the tariff to be fixed for the next cycle.

T. S. BALASUBRAMANIAN, Member (Finance)

[ADVT-III/4/Exty./143/2014]